



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2004/श्रावण 22, 1926

No. 143]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2004/SRAVANA 22, 1926

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2004

सं. 1-29/2004-बी एंड सी एस.—यथा-संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फाइल संख्या 13-1/2004-आर.इ.एस.टी.जी. से निर्गत दिनांक 9-1-2004 की अधिसूचना संख्या 39 द्वारा स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि जिन टैरिफों पर दूरसंचार (प्रसारण और केबल प्रचालन) सेवाएं प्रदान की जाएंगी उन्हें सरकारी राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2004 (2004 का क्रमांक 5)

### भाग I

#### नाम, विस्तार और प्रारंभ

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

- (i) इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2004 कहा जाएगा।
- (ii) यह आदेश पूरे भारत में लागू होगा।
- (iii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

### भाग-II

#### टैरिफ

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं टैरिफ (पहला संशोधन) आदेश, 2004 द्वारा यथा संशोधित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं टैरिफ आदेश 2004 के भाग II के खंड 2 में 'प्रभार (या प्रभारों)' शब्दों के पहले 'करों को छोड़कर' शब्द डाले जाएंगे।

### भाग III

#### 3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारत सरकार ने लोक सभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक, 2004 में सेवाकर बढ़ाने का और केबल सेवाओं में शिक्षा उपकर (cess) लगाने का प्रस्ताव किया है। चूंकि प्राधिकरण ने केबल टीवी सेवाओं की अधिकतम सीमा (सीलिंग) निर्धारित कर रखी है, अतः यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि, करों में वृद्धि को देखते हुए, केबल टीवी सेवाओं में वृद्धि की जाए या नहीं।

विनियमित मूल्यों में सामान्यतया करों को शामिल नहीं किया जाता। इस मामले में भी प्राधिकरण का आशय यही था कि प्रभारों की अधिकतम राशि (सीलिंग) में करों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस को स्पष्ट करने की दृष्टि से प्राधिकरण ने टैरिफ आदेश को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

आदेशानुसार,

राकेश कक्कड़, सलाहकार (बी. एंड सी. एस.)

[विज्ञापन III/IV/142/2004/असा.]

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2004

**No. 1-29/2004-B&CS.**—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India, 1997 as amended read with the Notification No. 39 dated 09-01-2004 issued from file No. 13-1/2004-RESTG. by the Government of India under clause (d) of Sub-section (1) of Section 11 and proviso to clause (k) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunications (Broadcasting and Cable Operation) Services shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

### **The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff (Second Amendment) Order, 2004 (5 of 2004)**

#### SECTION I

##### Title, Extent and Commencement

##### 1. Short title, extent and commencement :

- (i) This Order shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff (Second Amendment) Order 2004".
- (ii) The Order shall be applicable throughout the territory of India.
- (iii) The Order shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette.

#### SECTION II

##### Tariff

2. In clause 2 of Section II of The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff Order as amended by The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff (First Amendment) Order, 2004 after the words 'charges', the words "excluding taxes" shall be inserted.

#### SECTION III

##### 3. Explanatory Memorandum

The Government of India in the Finance Bill, 2004 as introduced in the Lok Sabha has proposed to increase the service tax and levy an educational cess on cable services. As the Authority has put a ceiling on the Cable TV service rates, a clarification has been sought that in view of the increase in the taxes, whether the cable TV service rates should be increased or not.

Regulated prices are generally exclusive of taxes and in this case also the intention of the Authority was to place a ceiling of the charges exclusive of taxes. To clarify the issue, the Authority has decided to amend the tariff order.

By Order,

RAKESH KACKER, Advisor (B&CS)

[ADVT. III/IV/142/2004/Exty.]